(ख) उक्त मामलों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने व्यक्तियों को आरोप-पत्र देकर उनके विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही शुरू की की गई है; और

(ग) सरकार ने देश की राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1993 तथा 1994 के दौरान अपहरण, हत्या, डकैती, लूट, चोरी तथा बलात्कार की दर्ज की गई घटनाओं की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें गिरफ्तार किया और जिनका चालान किया गया तथा जिनके विरुद्ध अभियोजन चलाया गया, संलग्न विवरण **(नीचे देखिए)** में दी गई है

(ग) दिल्ली में अपराध रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें महत्वपूर्ण स्थलों पर पिकेट्स स्थापित करना, आसूचना तंत्र को मजबूत करना, अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारना, चौकसी में बढ़ौत्तरी करना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक हथियारों के प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना, जांच के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देना, संचार नेट-वर्क का आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।

विवरण

	दर्ज किए गए मामलों की संख्या		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		चालान किए गए व्यक्तियों की संख्या	
	1993-94		1993	1994	1993	1994
1. अपहरण	636	784	401	458	352	314
2. हत्या	493	492	836	725	827	579
3. डकैती	27	19	112	78	108	64
4. लूट	269	347	293	357	248	262
5. चोरी	13154	13490	6702	6442	5707	3942
6. बलात्कार	315	309	441	432	418	339

दिल्ली वित्त निगम संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

477. श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ शीम अफ़ज़ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को दिल्ली वित्त निगम, नई दिल्ली के बारे में 21 जून, 1993 के उस लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन की जानकारी है; जिसमें दो करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्। (ख) और (ग) आंध्र बैंक फाइनेन-शियल सर्विसिज लिमिटेड द्वारा 200 लाख रुपए की मूलधन राशि का भुगतान कार्पोरेशन को कर दिया गया है। कार्पोरेशन द्वारा यह ... लिया गया है कि ए.बी.एफ.एस.एल. द्वारा इस राशि पर कार्पोरेशन को देय ब्याज का भुगतान तब ही किया जायेगा जब ए.बी.एफ.एस.एल. के वित्तीय स्रोत इस प्रकार के सभी इन्टर-कार्पोरेट जमा धारकों को भुगतान

करने की अनुमति देते हों। ए०बी०एफ०एस० एल० में निवेश से संबंधित मामले को कार्पोरेशन ने सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, को भेज दिया है।

Fencing of borders in Jammu region

478. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Centre is considering the proposal for fencing the international border along the Jammu frontier in view of the recent "spurt in infiltration" by the militants from Pakistan into the area;

(b) whether Government would accord priority to this proposal is view of the ISI threat to step up violence in the Jammu region;

(c) the estimated cost of the project and the phases in which it shall be taken up; and

(d) what other effective measures are being taken to thwart Pakistan's ISI fanning trouble in the Jammu region and breaking its age old secular fabric?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Yes, Sir. The total cost estimated for fencing (180 Km.) flood lighting (195.8 Kms) comes to about Rs. 71.76 crores. The work is expected to be completed by March, 1996.

(d) Government have initiated all necessary and appropriate steps to check smuggling of arms/ammunition including strengthening and deployment of para-military forces, their intensified patrolling, issue of sophisticated border surveillance equipments, gearing up State intelligence network and close coordination between various agencies, opening of new checok-posts and conducting of surprise checks, monitoring the activities of anti-social and anti-national elements etc.

बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान किया जाना

479. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में विशेषकर गाजियाबाद में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :(क)से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बंगलादेशी नागरिक उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ क्षेत्रों में चोरी-छिपे घुस आए हैं। ऐसे बंगलादेशी राष्ट्रिकों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि व चोरी छिपे प्रवेश करते हैं तथा स्थानीय जनसंख्या के साथ आसानी से मिल जाते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को इस आशय के स्थाई अनुदेश दिए गए हैं–कि वे अवैध बंगलादेशी नागरिकों का पता लगायें और उनको बंगलादेश लौटायें। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल की गश्त बढ़ाने, इसके वाटरविंग को मजबूत करने, विदेशी नागरिकों की रोकथाम (पी०आई० एफ०)/मोबाइल टास्क फोर्स (एम०टी०एफ०) नामक योजनाओं को मजबूत बनाने इत्यादि जैसे उपाय किए गए/किए जा रहे हैं ताकि घुसपैठ की कारगर रोकथाम की जा सके।

Report on Human Rights for the rear 1994

480. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the Amnestry International's report on Human Rights